

Government of India
Ministry of Communications and Information Technology
Department of Information Technology
Electronics Niketan
6, CGO Complex

New Delhi-110003
November 12, 2010

Notification

Policy on Open Standards

No. 2(32)/2009/EG-II WHEREAS, Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP), which seeks to create the right Governance and institutional mechanism, implement a number of Mission Mode Projects at the Center & State government

AND WHEREAS, Standards in e-Governance is considered priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications and also creation of Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance

AND WHEREAS under NeGP, GoI is promoting the usage of Open Standards to avoid any technology lock-in

AND WHEREAS a well laid Policy on Open Standards would play a critical role in adopting / evolving the Standards for the rapid, effective and efficient growth of e-Governance in India

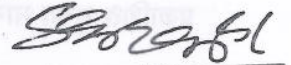
AND WHEREAS the Competent Authority on Standards has approved the Policy on Open Standards

NOW, this Department hereby notifies the use of Policy on Open Standards published on <http://egovstandards.gov.in> for the selection of Single and Royalty-Free (RF) Open Standard for a specific purpose with in a domain for e-Governance w.e.f the date of notification.

To

The Manager
Government of India Press
Faridabad (Haryana)


: Alongwith Hindi Version.


(S.S. Rawat)
Joint Director

o/c

Copy for information to:

1. All Secretaries, Government of India
2. Chief Secretaries of all the State Governments
3. Secretary (IT) of all the States.


(S.S. Rawat)
Joint Director

भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली
12 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

मुक्त मानदण्डों पर नीति

सं. 2(32)/2009-ईजी-II जबकि, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (इनईजीपी) चला रहा है, जिसमें सही शासन और संस्थागत तंत्र की स्थापना करने, केन्द्र और राज्य सरकार में कई मिशन मोड परियोजनाएँ कार्यान्वित करने की बात की गई है

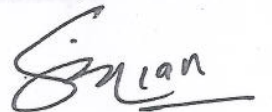
और जबकि, ई-शासन के मानदण्डों को प्राथमिकता प्राप्त कार्यकलाप माना गया है, जिससे सूचना के आदान-प्रदान और ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा के अविच्छिन्न अन्तर-प्रचालन में तथा ई-शासन के लिए मानदण्ड बनाने/अपनाने के लिए एनईजीपी के अंतर्गत संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का भी सुनिश्चय करने में सहायता मिलेगी

और जबकि, एनईजीपी के अंतर्गत भारत सरकार किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोधों को दूर करने के लिए मुक्त मानदण्डों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है

और जबकि, मुक्त मानदण्डों पर यथोचित रूप से निर्धारित एक नीति भारत में ई-शासन के तीव्र, प्रभावशाली एवं सक्षम विकास के लिए मानदण्ड अपनाने/तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी

और जबकि, मानदण्डों पर सक्षम प्राधिकारी ने मुक्त मानदण्डों संबंधी नीति को अनुमोदित कर दिया है

अब, यह विभाग एतद्वारा अधिसूचना की तारीख से ई-शासन के लिए एक डोमेन के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक ही और रायल्टी मुक्त (आरएफ) मुक्त मानदण्ड के चयन के लिए <http://egovstandards.gov.in> पर प्रकाशित मुक्त मानदण्डों संबंधी नीति को अधिसूचित करता है।



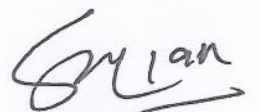
(एस.एस.रावत)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार प्रेस
फरीदाबाद (हरियाणा)

सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी सचिव ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
3. सभी राज्यों के सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) ।



(एस.एस.रावत)
संयुक्त निदेशक